(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवासों के लिए दिए गए ऋण**

2015. **डा० बापू कालदाते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास सुविधा के लिए कोई ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने लोगों को कितनी-कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है ; और

(ग) ऋण दिए जाने के निबंधन और शर्तें क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) राष्ट्रीय आवास बैंक अलग-अलग व्यक्तियों को सीधे ही आवास वित्त प्रदान नहीं करता है । राष्ट्रीय आवास बैंक अपने मार्गनिर्देशों के अनुसार संविस्तरित किए गए पात्र ऋणों के संबंध में सभी पात्र प्राथमिक ऋणदाताओं (अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आवास वित्त संस्थायें और राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियां) को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है ।

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक की विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं (राज्य स्तरीय विकास बैंकों द्वारा चलाए गए विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचर के लिए अंशदान सहित) के अंतर्गत 8.50 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए उसने जून, 1992 तक कुल 1198.09 करोड़ रुपए का संवितरण किया ।

(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक नए आवास एककों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए आवास ऋणों के संबंध में 100% पुनर्वास प्रदान करता है :—(i) 40 वर्ग मी० से अनाधिक के निर्माण क्षेत्रों के लिए 2 लाख रुपए तक (ii) 40 वर्ग मी० से अधिक के निर्मित क्षेत्र लेकिन 2 लाख रुपए से अनाधिक की लागत वाले एककों के लिए ऋण राशि तक और (iii) बड़ी मरम्मतों सहित उन्नयन के लिए 30,000 रुपए तक ,राष्ट्रीय आवास बैंक, आकार/लागत पैरामीटरों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार, तैयार की गई उन समन्वित भूमि विकास एवं आश्रय परियोजनाओं के लिए, जो (i) सार्वजनिक एजेंसियों, (ii) सहकारी समितियों, (iii) व्यावसायिक विकासकों द्वारा और (iv) नियोजकों द्वारा किराया आवास के लिए शुरू की जा सकती है, भी 100 पुनर्वित्त प्रदान करता है ।

**RBI Inquiry into Inspection System through a Consultancy Firm**

2016. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the RBI Governor ordered an inquiry into the inspection systems of the RBI by a Management and Consultancy firm;

(b) if so, what are the terms of reference, name of the firm and fees settled;

(c) whether the firm has submitted its report;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (e) The infromation is be ing collected and will be laid on t he Table of the House.